

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16-5-18	<p>आज्ञाकारी के द्वारा कृष्णमन्य कार्यालय की स्थापना। कृष्णमन्य कार्यालय का स्थापना के लिए राजकीय भूमि का आवंटन करके पुरी गरी करके कार्य दिनांक 12-6-18 को प्रेषित</p>	
12-6-18	<p>आज्ञाकारी के द्वारा कृष्णमन्य कार्यालय की स्थापना के लिए राजकीय भूमि का आवंटन करके कार्य दिनांक 25-6-18 को प्रेषित है।</p>	
25-6-18	<p>आज्ञाकारी के द्वारा कृष्णमन्य कार्यालय की स्थापना। राजकीय भूमि का आवंटन करके कार्य दिनांक- 06-2-18 के द्वारा कार्य दिनांक 06-2-18 को प्रेषित है। आज्ञाकारी के द्वारा कृष्णमन्य कार्यालय की स्थापना के लिए राजकीय भूमि का आवंटन करके कार्य दिनांक 16-7-18 को प्रेषित है।</p>	
16-7-18	<p>आज्ञाकारी के द्वारा कृष्णमन्य कार्यालय की स्थापना। राजकीय भूमि का आवंटन करके कार्य दिनांक 06-2-18 के द्वारा कार्य दिनांक 06-2-18 को प्रेषित है। आज्ञाकारी के द्वारा कृष्णमन्य कार्यालय की स्थापना के लिए राजकीय भूमि का आवंटन करके कार्य दिनांक 16-7-18 को प्रेषित है।</p>	

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

अपील संख्या : 64/2016

1. श्रीमती नाना देवी पत्नी स्व० श्री धासी, जाति-बलाई, निवासी-हरिरामपुरा, तहसील-फागी।
2. मंजू पुत्री धासी, जाति-बलाई, निवासी-हरिरामपुरा, तहसील-फागी।
3. कजोड पुत्र धासी, जाति-बलाई, निवासी-हरिरामपुरा, तहसील-फागी।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. तहसीलदार, (भू-अभिलेख) फागी, जिला-जयपुर।
2. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी गोविन्दराम, जाति-रैगर, निवासी-50/429, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।
3. श्रीमती ममता पत्नी चन्द्रप्रकाश पुत्री फूलाराम, जाति-बलाई, निवासी-चितौड।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आज्ञा दिनांक 01.01.2013 तहसीलदार, फागी दिनांक नामान्तरकरण संख्या 230 ग्राम हरिरामपुरा)

उपस्थित:-

1. श्री महावीर प्रसाद कसवा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
3. रेस्पोडेन्ट सं० 2 व 3 असालतन/वकालतन अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 16.07.2018

तहसीलदार, फागी ने ग्राम-हरिरामपुरा की आराजी ख०सं० कुल किता 04 रकबा 13 बीधा 11 बिस्वा हि० 1/4 शेष बदस्तूर एवं आराजी खसरा सं० कुल किता 02 रकबा 04 बीधा 15 बिस्वा हि० 1/8 शेष बदस्तूर का नामान्तर- करण विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2012 के आधार पर क्रेत्री सुशीला देवी पत्नी गोविन्दराम, जाति-रैगर, निवासी-50/429, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर के हक में दिनांक 01.01.2013 को स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई हैं।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की

गई।



(Handwritten signature)

उभय-पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद कसवां का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि-विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा ना०सं० 230 दिनांक 01.01.2013 स्वीकार किये जाने से पूर्व सम्बन्धितों को सुनवाई का नोटिस/अवसर नहीं दिया गया। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि सम्बन्धितों को सुनवाई का नोटिस व साक्ष्य/सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया जावे किन्तु विचारण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका नहीं दिया गया। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 01.01.2013 एकतरफा पारित किये जाने से निरस्तनीय है जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट्स का कब्जा-काश्त है मौके की जांच नहीं की गई यदि मौके की जांच की जाती तो अवैध कार्यवाही हो ही नहीं सकती थी। वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को सर्वप्रथम दिनांक 20.02.2012 को उस समय हुई जब अपीलान्ट्स ने विरासत के नामान्तरकरण हेतु प्रशासन गांवों के संग कैम्प में प्रार्थना पत्र दिया तो पटवारी ने बताया कि वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 05.10.2012 को रेस्पोंडेन्ट सं० 3 के हक में व तत्पश्चात् विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट सं० 2 के हक में दिनांक 01.01.2013 को खोला जा चुका है। जिस पर नकल लिये जाने पर सारी तथ्यों की जानकारी हुई और अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। वादग्रस्त आराजी ख०सं० कुल कित्ता 04 रकबा 13 बीधा 11 बिस्वा एवं आराजी खसरा सं० कुल कित्ता 02 रकबा 04 बीधा 15 बिस्वा हि० 1/2 ग्राम-हरिरामपुरा अपीलान्ट्स सं० 1 के पति व अपीलान्ट्स सं० 2, 3 के पिता श्री धासी की खातेदारी काश्तकारी आराजी है। खातेदार धासी की दिनांक 28.11.2011 को मृत्यु हुई है। मृतक धासी की पत्नी अपीलान्ट्स नाना देवी, मंजू पुत्री, कजोड दत्तक पुत्र वारिस है। धासी के एक पुत्र दुर्गालाल भी था जिसका विवाह ममता से हुआ था परन्तु दुर्गालाल की मृत्यु दिनांक 06.12.2006 को अर्थात् खातेदार धासी की मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी और मृतक दुर्गालाल के कोई संतान नहीं थी। मृतक दुर्गालाल की पत्नी रेस्पोंडेन्ट सं० 3 ममता ने मृतक दुर्गालाल के पिता धासी के जीवनकाल में ही अन्य से पुनर्विवाह कर लिया था अर्थात् खातेदार धासी के जीवनकाल में ही मृतक दुर्गालाल की विधवा पत्नी ममता द्वारा पुनर्विवाह कर लिये जाने के कारण खातेदार धासी की संवृत्ति में विधवा पुत्रवधू ममता का कोई विधिक अधिकार नहीं रहा। इसके बावजूद भी रेस्पोंडेन्ट सं० 3 ममता ने राजस्व कारकूनान से मिलीभगत कर व



(Handwritten signature)

गलत-झूठा सजरा खानदान (कुर्सीनामा) पेश कर सही तथ्यों को छिपाकर अवैध रूप से नामान्तरकरण सं० 217 दिनांक 05.10.2012 को अपने हक में खुलवाकर तस्दीक करा लिया जो अवैध व निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण सं० 217 के आधार पर रेस्पोंडेन्ट सं० 2 के हक में दिनांक 18.10.2012 को किया गया विक्रय पत्र विक्रेता को वादग्रस्त आराजी के बिना अधिकार निष्पादित किया गया है जो अवैध व शून्य है। अवैध व शून्य विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया नामान्तरकरण सं० 230 दिनांक 01.01.2013 स्वतः ही अवैध व शून्य है। अतः अपील-अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 01.01.2013 नामान्तरकरण सं० 230 में रेस्पोंडेन्ट सं० 2 के हक में किया गया इन्द्राज निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 01.01.2013 नामान्तरकरण सं० 230 ग्राम-हरिरामपुरा विधि-विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई हैं। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 01.01.2013 नामान्तरकरण संख्या 230 ग्राम- हरिरामपुरा वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार रेस्पोंडेन्ट सं० 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किये जाने के आधार पर भरा जाकर तस्दीक किया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2012 अपने आप में स्पष्ट एवं वैधानिक पंजीकृत दस्तावेज है। सरकार द्वारा निर्धारित राशि पंजीयन कार्यालय में जमा कराई जाकर सक्षम अधिकारी उप पंजीयक से विक्रय पत्र को पंजीकृत करवाया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र को किसी के द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया है। आज भी पंजीकृत विक्रय पत्र का वैधानिक अस्तित्व है। काश्तकारी-खातेदारी आराजी के सद्भाविक खातेदार द्वारा विक्रय पत्र तहरीर किया गया है। खातेदार को पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी आराजी को विक्रय करे/दान करे/गिफ्ट करे अथवा अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित करे, स्वयं काश्त करे अथवा किसी अन्य से काश्त करावे। कानून में प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुए स्वयं की खातेदारी आराजी का विक्रय पत्र पंजीकृत कराया गया है। विक्रय पत्र की परीक्षण किये जाने के पश्चात् सक्षम अधिकारी उप पंजीयक द्वारा विक्रय पत्र को पंजीकृत किया गया है। मृतक धासी की विरासत से रेस्पोंडेन्ट सं० 3 को राजस्व अभिलेख में प्राप्त हुये खातेदारी अधिकारो को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया है। राजस्व अभिलेख में रेस्पोंडेन्ट सं० 3 का



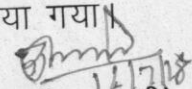
[Handwritten signature]

नाम दर्ज होने और रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान किये जाने के फलस्वरूप पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार विक्रय पत्र एवं नामान्तरकरण के फलस्वरूप रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 में निहित हो चुके हैं। नामान्तरकरण एक समेरी प्रोसिडिंग है। नामान्तरकरण को अपीलान्ट्स द्वारा चुनौती दी जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के खातेदारी अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायोचित रूप से नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। अतः अपील-अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। उभय-पक्षों की बहस से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार-काश्तकार द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के हक में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है और इसके आधार पर ही चुनौती अधीन आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 01.01.2013 ग्राम-हरिरामपुरा स्वीकार की गई है। चुनौतीधीन आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 230 ग्राम हरिरामपुरा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है, पंजीकृत विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया है विचारण प्रकरण में पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर किसी के द्वारा निरस्त कराया गया हो अर्थात् पंजीकृत विक्रय पत्र का वैधानिक अस्तित्व विद्यमान है। हमारा मत है कि नामान्तरकरण एक समेरी प्रोसिडिंग्स है, नामान्तरकरण से हक-हकूक तय नहीं होते हैं, अपीलान्ट्स के वादग्रस्त आराजी में कोई हक-हकूक उत्पन्न होते हैं तो अपीलान्ट्स को सक्षम न्यायालय में चाराजोई की जानी चाहिए। अतः उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 01.01.2013 नामान्तरकरण संख्या 230 ग्राम हरिरामपुरा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं पाते हैं। अतः अपील-अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आज्ञा यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।




(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर